

کے جو غریب ہیں۔ انکی سرکشی کی گارنٹی  
کی جائے اور جسکے ساتھ ہی ساتھ اس  
علاقے میں ہیں اس پر کار کی گھنٹا نہیں  
تھیں گی۔ پولیس اور سرکشی کی طرف سے  
اسکی گارنٹی ہو۔ ہم یہ چاہیں گے کہ اسکی  
ویو سٹیا سرکار کے اسکی اور دیوانہ کرشت  
کرنے کیلئے میں نے آپ کے مادہ عیم کے اور  
سوں کے مادہ عیم کے یہ سوال اٹھا چکا ہے تاکہ  
لیڈر سرکار بھی اس دشمن کوئی کارکر  
قدم اٹھائے۔ شکریہ۔ ختم شد۔

RE: SALE OF SUGAR MILLS IN  
UTTAR PRADESH

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल):  
धन्यवाद उपसभापति महोदय। कल उत्तर प्रदेश के बजट  
की चर्चा करते हुए हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना  
किसानों की समस्यायें दिलाया था। परसों मैं देखरिया  
जिला में गई थी और वहाँ गन्ना किसानों का एक  
डेलीगेशन मुझसे आकर मिला और अपनी समस्याओं के  
बारे में उन्होंने मुझे बताया।

माननीया, किसान ऋण लेकर खेती करते हैं लेकिन न  
तो उन्हें समय पर खाद मिलती है, न कीटनाशक दवाइयाँ  
मिलती हैं और गन्ना जब खेत में खड़ा हो जाता है तो  
अंदाज़ लगाया जा सकता है कि उनकी क्या हालत  
होगी। उधर गवर्नमेंट द्वारा 14 सरकारी मिलों को बेचने  
के बाद से स्थिति और भी खराब हो गई है और जो  
निजी मिल-मालिक हैं, वे अपनी मनमानी कर रहे हैं।  
राज्यपाल ने गन्ने की कीमत 70 से 72 रुपये क्विंटल  
और 74 रुपये क्विंटल कर दी। इसके खिलाफ चीनी  
मिल-मालिकों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया  
और उन्हें रुके भी मिल गया। इससे स्थिति और भी गंभीर  
हो गई है। अब जब गन्ना-किसान मिलों में अपना गन्ना  
बेचने जाते हैं तो मिल-मालिक उनके साथ बारगेनिंग  
करते हैं कि 40, 42 अथवा 62 रुपये तक ही वे लेंगे  
अन्यथा उन्हें जो पुरजी दी जाती है उस पर, रेट किस  
नहीं है इसलिए पेंडिंग रेट की मोहर लगा दी जाती है

और उन्हें बहुत ही मजबूरी का सामना करना पड़ता है।  
ऐसी हालत में आपके सामने यह माँग रखना चाहूँगी कि  
जल्दी से जल्दी उनकी बकाया रकम का भुगतान किया  
जाए। प्रधान मंत्री ने भी कुछ दिन पहले आश्वासन दिया  
था कि जो बकाया है, उसका भुगतान किया जाएगा  
किन्तु अब तक सरकारी मिलें भी 50 परसेंट से अधिक  
भुगतान नहीं कर पाई हैं। ऐसे हालात में मैं आपके  
माध्यम से तीन बातें रखना चाहूँगी कि:—

1. खेत में खड़ी फसल के आधार पर सट्टा नीति  
तय की जाए।
2. तुरन्त पिछले और वर्तमान बकायों का निबटारा  
किया जाए, सरकार द्वारा घोषित मूल्य के आधार पर।  
और
3. तौल में जो धाँधली होती है, उसके लिए प्रत्येक  
तौल कंटे पर जिला गन्नाधिकारी द्वारा एक सर्वेक्षक  
नियुक्त किया जाए, जिससे यह धाँधली न हो।  
धन्यवाद।

RE: RELEASE OF 39 INDIAN  
CHILDREN DETAINED IN PAKISTANI  
JAILS

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa):  
Madam, I would like to raise the plight of 40  
Indian children who are languishing in the  
Pakistani jails. I gave this notice on Monday,  
but I am told that the attention of the House  
was already focussed on this issue. Mr.  
Gujral is aware of this. His Ministry is  
involved in this. Mr. Gujral should intervene  
in the matter and see that these children are  
released from the Pakistani jails.

Madam, this matter was raised by the  
BBC. The Amnesty International has taken  
up this matter. But there is no attempt by the  
Government of India to see that these  
children are brought back to India. These  
children were taken away from the  
Saurashtra-Kutch region by fishing boats  
which were on long voyages.

The hon. Supreme Court had recently  
delivered a landmark judgement on child  
labour. I want to know from the Minister of  
External Affairs the steps being taken by  
him to bring back these children to India and  
to rehabilitate them. At the

same time, I want also to know the steps the Central Government has taken to direct the State Government to stop child labour.

THE DEPUTY CHAIRMAN: How are they in Pakistan?

SHRI JOHN F. FERNANDES: They were taken away by the fishing boats. The Pakistani marines had arrested them. They were put in the Pakistani jails and they have been in the Pakistani jails for the last three years. When they were taken away, they were about 8 years. Now they are 11 years old, very young boys. The Central Government is doing nothing about it. They are just languishing in Karachi jails. Out of the 40 boys, one boy died. There are now 39 boys who are languishing there, in some charitable organisations. But the Foreign Minister knows about it. But no attempt has been made by the Government to bring them back to India. I want to have the reaction of the Minister of External Affairs. Mr. Gujral knows about it. I would like him to see that an authority is constituted by the Government of India to implement the direction of the Supreme Court, to implement the latest decision of the Supreme Court banning child labour.

Thank you, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You sec, this is a very serious matter. The children were smuggled or they were taken away by force. They had been arrested by the Pakistani authorities. I think our Government should take...

SHRI JOHN F. FERNANDES: Madam, they were languishing in prison and nothing was done by the Government.

THE DEPUTY CHAIRMAN: No, no. We should do something. Our defence Minister is here representing the Government.

मुलायम सिंह जी, हिंदुस्तान के 39 बच्चे पाकिस्तान की जेलों में हैं। मछुआरे लोग उनको अपनी बोट्स में

यहां से ले गए थे, वे पकड़े गए समुंदर में और वे जेलों में बंद हैं।

SHRI JOHN F. FERNANDES: No, Madam. They have been got released by Amnesty International and they are now with the NGOs. They have to be brought back.

उपसभापति: ऐमनेस्टी इंटरनेशनल ने उनको छोड़ दिया है और अब वे एन०जी० ओज० के पास हैं। उनको वापस हिंदुस्तान आना चाहिए। इसके लिए सरकार को कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए।

SHRI RAGHAVJI (Madhya Pradesh): Madam, I think the whole House is...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, the whole House and I think the whole country would like the children to be back.

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव): उपसभापति महोदया, कल सभाचारपत्रों में जो आया था और हमें और भी जो जानकारी मिली थी, उसके बाद हमने कल वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की थी और मैं कल तक विदेश मंत्री जी से बात करके उन्हें छुड़ाने का प्रयास करूंगा।

श्री एन०के०पी० साल्वे (महाराष्ट्र): महोदया, रक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है, हम इनके बहुत ऐहसानमंद हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन यह मामला ऐक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के दायरे में आता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले में उन्हें डायरेक्शन दें।

उपसभापति: ऐक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इस वक्त यहां नहीं हैं, इसीलिए मैंने रक्षा मंत्री जी से कहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव: महोदया, मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं कल तक विदेश मंत्री जी से बात करके उन्हें छुड़ाने की कोशिश करूंगा।

SHRI N.K.P. SALVE: Madam, ...

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHA-JIRAO SHINDE (Maharashtra): He said that he was taking the responsibility. He said that he would talk to the Minister of External Affairs.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is a meeting of the Foreign Ministers of SAARC countries today or tomorrow. I

think the Foreign Minister can take up this issue there.

Today we have a lunch hosted by the Chairman for the new Members. So, I will adjourn the House three minutes before for the new Members to reach there. Some of them are here and some of them have already gone.

I also want to make an announcement that all the Zero Hour submissions and Special Mentions which are pending and for which permission has been granted, will be taken up after the Short Duration Discussion. We want to clear all the business that is pending before we adjourn the House *sine die* in two days' time. All the pending matters which the Members feel...

AN HON. MEMBER: What about special mentions?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I said that Zero Hour submissions and Special Mentions will be taken up after the Short Duration Discussion so that whatever matters you want to raise about your constituencies are finished before we adjourn the House *sine die* in two days. You should not go back home saying that you wished to raise it.

The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at fifty-eight minutes past twelve of the clock.

2.00 P.M.

*The House re-assembled after lunch at five minutes past two of the clock, The Vice-Chairman (Shri MD. Salim) in the Chair.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We will take up Short Duration Discussion.

## SHORT DURATION DISCUSSION

### The Steep Rise in Prices of Essential Commodities

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली)

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह सरकार जब बनी थी लगभग छह माह पूर्व तो उस समय इसे जनता का समर्थन तो था नहीं और एक तिकड़म और भानुमती के पिटारे की तरह तेरह दिशाओं में दौड़ने वाले घोड़ों से खींचे गए रथ की तरह से तेरह दलों की यह सरकार बनी थी परंतु इसके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वे हम्बल फार्मर हैं, एक विनोत किसान हैं। कांग्रेस पार्टी और जनता दल का समर्थन इस सरकार को प्राप्त है और कम्युनिस्ट पार्टी भी इसका समर्थन कर रही है। तो लोगों को आशा थी कि कम से कम गरीबों और किसानों का यह सरकारी शायद समर्थन करेगी, उनको कुछ राहत पहुंचाएगी। परंतु उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार के छह महीने के काल में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जमाखोरों को, मुनाफ़ाखोरों को, दलालों को, बिचौलियों को, पूंजीपतियों को और बड़े-बड़े धन सेठ किसानों को और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है गरीबों को, झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले, स्लम में रहने वाले लोगों को। सबसे ज्यादा खून चूसा गया है आम आदमी का, किसान का और उसको यह नुकसान पहुंचाया गया। आटे और गेहूं का जो पिछले दिनों सैकड़ल हुआ, जो महंगाई हुई, यह आजाद हिंदुस्तान का शायद सबसे बड़ा घोटाला है। इससे पहले आटे और गेहूं की कीमतों में इतना बड़ा घोटाला, इतना भ्रष्टाचार और इतना निक्मामाफन किसी सरकार ने नहीं दिखाया। इन पिछले दो महीनों में ही गरीब आदमी की जेब से करीब पांच हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि निकल गई और बड़े-बड़े जमाखोरों के पास पहुंच गई। मैं इस बात का जिक्र नहीं कर रहा हूं कि रुपए की कीमत जैसा कि अखबार में पिछले दिनों आया था, 5.9 पैसे रह गई है क्योंकि यह सरकार उसकी पूरी जिम्मेदारी तो नहीं ले सकती। यह तो 1962 के बाद, बेस ईयर 1962 को मानकर, यह 5.9 पैसे रह गई। यह सरकार तो छह महीने की है लेकिन इस समय जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वह 6.8 परसेंट है और जब यह सरकार बनी थी तब यह 4.77 परसेंट था। तो 4.77 परसेंट छह महीने के अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ा है परंतु होलसेल इंडेक्स हिंदुस्तान के आम आदमी की कीमतों का कोई आईना नहीं है। यह उसका कोई शीशा नहीं है। वह है कंप्यूमर प्राइस इंडेक्स और कंप्यूमर प्राइस इंडेक्स, अक्टूबर के महीने का जो